श्री मंगुभाई पटेल

राज्यपाल, मध्यप्रदेश

का

अभिभाषण

मध्यप्रदेश विधानसभा अधिवेशन

अग्रहायण–पौष, मार्ग शुक्ल 8, शक 1945 भोपाल, बुधवार 20 दिसम्बर, 2023

माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यगण,

1. सोलहवीं विधानसभा के प्रथम सत्र में आप सभी का हृदय से स्वागत, वंदन एवं अभिनन्दन।
2. निर्वाचन, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। मुझे यह कहते हुए गर्व और प्रसन्नता है कि मध्यप्रदेश में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व की सफल पूर्णाहूति के लिए राज्य के सभी सम्माननीय मतदाता, निर्वाचन आयोग, सभी राजनीतिक दल, शासन-प्रशासन तंत्र एवं मीडिया बधाई के पात्र हैं।
3. इस विधानसभा निर्वाचन में मध्यप्रदेश के इतिहास का सर्वाधिक मतदान होना, न केवल लोकतंत्र में जन-जन की प्रबल आस्था का प्रतीक है, बल्कि माननीय मोदी जी की गारंटी, सरकार के कार्यों और संकल्पों के प्रति जनता के अटूट विश्वास का परिचायक भी है। माननीय प्रधानमंत्रीजी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जनता की जिंदगी को बदलने का मिशन पूरी तरह सफल एवं सार्थक सिद्ध हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि चुनाव जीतने से भी अधिक महत्वपूर्ण है जनता का दिल जीतना। मेरी

सरकार हृदय प्रदेश की जनता को अपने हृदय में बसाकर उनके कल्याण के लिए अनवरत कार्य करेगी।

4. मेरी सरकार ने कार्यभार ग्रहण करते ही आजादी के अमृतकाल में प्रदेश की साढ़े 8 करोड़ जनता के लिए विकसित भारत हेतु विकसित मध्यप्रदेश के निर्माण के नये विज़न और नये मिशन पर नई ऊर्जा, नये उत्साह, नये उल्लास, नई उमंग और नये संकल्प के साथ काम करना प्रारंभ कर दिया है। "सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास और सबका प्रयास"- माननीय प्रधानमंत्रीजी के इस मूल मंत्र को लक्ष्य बनाकर मध्यप्रदेश को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प-पत्र-2023, मेरी सरकार ने आत्मसात कर लिया है।

5. माननीय प्रधानमंत्रीजी के गौरवशाली नेतृत्व में विगत साढ़े 9 वर्षों में भारत में "माई-बाप सरकार" के युग की समाप्ति और "सेवक सरकार" के युग का प्रारंभ हुआ है। गरीब और वंचित, एक जमाने में जिनकी कोई पूछ-परख नहीं थी, प्रधानमंत्रीजी उन्हें पूछते भी हैं और पूजते भी हैं। माननीय प्रधानमंत्रीजी ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि देश के गरीब, देश के किसान, देश की नारी शक्ति और देश के युवा ही उनकी नजरों में सबसे बड़े VIP हैं। मेरी सरकार ने भी इससे प्रेरणा लेकर जन-जन के सुख-दुःख को अपना सुख-दुःख मानने और जनता की

आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संपूर्ण शक्ति के साथ समर्पित भाव से कार्य करने का प्रण लिया है।

6. आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की 140 करोड़ जनता को अपना परिवार माना है और जनता से उनका भावनात्मक रिश्ता इतना प्रगाढ़ है कि आम आदमी को इस बात का पूरा भरोसा है कि मोदी जी की गारंटी ही, हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी है। जहाँ दूसरों की उम्मीदें ख़त्म होती हैं, वहीं से मोदीजी की गांरटी शुरू होती है। यह निश्चय ही प्रसन्नता का विषय है कि जनता के कल्याण और देश को आगे बढ़ाने के शुभ-संकल्प के साथ "विकसित भारत संकल्प यात्रा"का मध्यप्रदेश में 16 दिसंबर से भव्य शुभारंभ हो गया है। मध्यप्रदेश में इस यात्रा की कमान स्वयं यहाँ की जनता ने संभाल ली है। मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी प्रदेश के नगर-नगर और गाँव-गाँव तक पहुंच रही है और प्रदेश की जनता दीप जलाकर, फूल बरसाकर, रंगोली बनाकर और बड़ी संख्या में यात्रा में भाग लेकर उसका उत्साह के साथ स्वागत कर रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम स्वनिधि योजना आदि हितग्राहीमूलक योजनाओं के लाखों लाभार्थी अपनी जिंदगी बदलने के अनुभव सुना रहे हैं, तो दूसरी तरफ

यह यात्रा सभी पात्र हितग्राहियों तक पहुँचने का माध्यम बन रही है, जो योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए थे। मेरी सरकार, इस यात्रा के दौरान केंद्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति को दिलाते हुए शत-प्रतिशत सेचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करेगी।

7. मेरी सरकार के लिए सुशासन केवल एक शब्द नहीं, बल्कि उसके हर अक्षर को सच्चे अर्थों में चरितार्थ करने का मंत्र है। पारदर्शी, उत्तरदायी, त्वरित, संवेदनशील और कर्तव्यनिष्ठ कार्य-संस्कृति शासन तंत्र के प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित करना मेरी सरकार का सर्वोपरि लक्ष्य है। यही कारण है कि मेरी सरकार ने कार्यभार संभालते ही 01 जनवरी, 2024 से साइबर तहसील की व्यवस्था को प्रदेश के सभी 55 जिलों में लागू करने का क्रांतिकारी निर्णय लिया है। मेरी सरकार संपदा-2 सॉफ्टवेयर भी संपूर्ण प्रदेश में शीघ्र लागू करने जा रही है, जिसके माध्यम से डिजिटल रजिस्ट्री की प्रक्रिया सरल और सुगम बनेगी।

8. गंभीर अपराधों में लिप्त रहे आदतन अपराधियों को कठोर से कठोर दण्ड दिलवाने तथा ऐसे अपराधियों द्वारा माननीय न्यायालय से प्राप्त जमानत के लाभ के दुरूपयोग को रोकने, अनुपयोगी और खुले बोरवेल से होने वाली दुर्घटनाओं को

सुनियोजित रणनीति बनाकर रोकने, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अवैधानिक प्रयोग पर नियंत्रण तथा मांस-मछली के अनियंत्रित क्रय-विक्रय को प्रतिबंधित करने के लिए अभियान के रूप में कार्यवाही प्रारंभ करके मेरी सरकार ने यह स्पष्ट संदेश देने का प्रयास किया है कि सुशासन और कानून के राज से बढ़कर और कोई नहीं है।

9. संकल्प-पत्र-2023 मध्यप्रदेश की जनता को माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी भी है और विकसित मध्यप्रदेश के निर्माण का विज़न डॉक्यूमेंट भी। प्रसन्नता का विषय है कि मेरी सरकार ने संकल्प-पत्र के बिंदुओं को धरातल पर उतारने का काम प्रारंभ कर दिया है। सरकार द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहण की दर 3 हजार रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4 हजार रुपए प्रति मानक बोरा कर दी गई है। इस निर्णय से 35 लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहकों को 162 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त होगा। मध्यप्रदेश के मन में बसे माननीय मोदी जी की हर गारंटी को पूरा करने के उद्देश्य से संकल्प-पत्र के प्रत्येक बिंदु को समय-सीमा में क्रियान्वित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

10. मेरी सरकार अगले 7 वर्ष में मध्यप्रदेश को 45 लाख करोड़ रुपए की अर्थ-व्यवस्था बनाने और लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश से प्रतिव्यक्ति आय को दुगुना करने के लक्ष्य के

साथ कार्य कर रही है। वर्ष 2022-23 के प्रचलित भावों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद की वर्तमान वृद्धि दर 16.43% को और आगे बढ़ाने के लिए सरकार तेजी से प्रयास करेगी।

11. प्रधानमंत्री जी के सबल नेतृत्व में नये भारत की नई संसद में पारित "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" वस्तुत: भारतीय नारी की शक्ति और कीर्ति को संपूर्ण विश्व में ज्योतिर्मय करने का जयघोष है। प्रदेश में लगभग 20 वर्षों के विश्वास और विकास को आगे बढ़ाते हुए नारी उत्थान के हर संकल्प को पूरा करना मेरी सरकार की प्राथमिकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में अपने बलबूते पर आगे बढ़ने का उल्लेखनीय अवसर प्रदान किया है। सरकार द्वारा अब तक लगभग 5 लाख स्व-सहायता समूहों से 61 लाख से अधिक महिलाओं को जोड़ा जा चुका है। महिलाओं के सामाजिक, आर्थिकएवं राजनैतिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से लागू की गईं केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्रदेश की करोड़ों माताओं-बहनों और बेटियों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं।

12. किसानों की समृद्धि ही प्रदेश की सुख-समृद्धि का आधार है। मेरी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, समर्थन मूल्य पर उपार्जन, कृषि

अधोसंरचना निधि आदि विभिन्न किसान कल्याण योजनाओं के अंतर्गत विगत साढ़े 3 वर्षों में किसानों के खातों में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष में प्रदेश में श्रीअन्न उत्पादों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मिशन मोड में काम किया जा रहा है। प्रदेश में इस वर्ष मिलेट फसलों का कुल क्षेत्रफल 5 लाख 64 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 6 लाख 24 हजार हेक्टेयर तथा कुल उत्पादन 11 लाख 97 हजार मीट्रिक टन से बढ़कर 13 लाख 11 हजार मीट्रिक टन तक पहुंचने की संभावना है।

13. राज्य सरकार के प्रयासों से आज मध्यप्रदेश संतरा, धनिया, मसाले एवं औषधीय पौधों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश के कृषकों को रोगमुक्त और उच्च गुणवत्ता के आलू बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश की प्रथम ऐरोपोनिक यूनिट एवं टिशूकल्चर लैब की स्थापना ग्वालियर में की जा रही है। प्रदेश में 8 करोड़ रूपये से अधिक की लागत के 12 उद्यानिकी कृषक प्रशिक्षण केन्द्र बनाये गये हैं। नर्सरियों के कुशल प्रबंधन हेतु पहली बार अत्याधुनिक नर्सरी पोर्टल तैयार किया गया है।

14. मछली उत्पादन में लगातार उल्लेखनीय वृद्धि के लिये भारत सरकार द्वारा ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस में मध्यप्रदेश के सिवनी और बालाघाट जिले को उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया है।

प्रदेश में अब तक 87 हजार से अधिक मछुआ क्रेडिट कार्ड स्वीकृत करते हुए मध्यप्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है।

15. मेरी सरकार मुख्यमंत्री गौ-सेवा योजना, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदाय, चलित पशु चिकित्सा इकाई योजना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन और मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम जैसी अभिनव योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर किसानों और पशुपालकों को लाभान्वित करने का काम निरंतर कर रही है।

16. भारत सरकार के "सहकार से समृद्धि अभियान" अंतर्गत प्रदेश की 4 हजार 500 से अधिक सहकारी संस्थाओं का 145 करोड़ रुपए की लागत से कम्प्यूटरीकरण कराया जा रहा है। किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर 3 लाख रूपये तक का अल्पावधि कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के आधारभूत ढ़ाँचे को सुदृढ़ करने के लिए कृषि अधोसंरचना कोष से 1 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण सुविधा प्रदान की गई है।

17. कमजोर और वंचित वर्गों के कल्याण का संकल्प राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा, जनजातीय कल्याण के संकल्प की प्रबल अभिव्यक्ति

है। अगले 5 वर्षों में जनजातीय कल्याण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के व्यय किए जाने का लक्ष्य है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के भाई-बहनों के सर्वांगीण विकास हेतु क्रियान्वित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण हेतु राजभवन में पृथक जनजातीय प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। पेसा नियमों के क्रियान्वयन से 1 करोड़ से अधिक जनजातीय समुदाय लाभांवित हुआ है। जनजातीय समुदाय के लिए विभिन्न स्व-रोज़गार योजनाओं के माध्यम से 60 करोड़ रुपएकी सहायता प्रदान की गई है। जनजातीय सेनानियों के बलिदानों की स्मृति को अमर बनाने के लिए 2 नये संग्रहालयों का निर्माण किया जा रहा है। मेरी सरकार सभी जनजातीय विकासखंडों में सिकल सेल एनिमिया की जाँच और उपचार के मिशन को और तेजी से तथा प्रभावी रूप से क्रियान्वित करेगी। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत 10 लाख से भी अधिक लाभार्थियों को जेनेटिक काउंसिलिंग कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। मेरी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जी के वर्ष 2047 तक सिकल सेल उन्मूलन संकल्प की प्राप्ति के लिए आगामी 2 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में 37 लाख लोगों की जाँच की जावेगी।

18. प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य 1690 ग्रामों के समेकित विकास हेतु प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें मध्यप्रदेश, देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य बना